Capacity of Foodgrains Storages in the Country

1539. SHRI BHUPINDER SINGH MANN. Will the Minister of FOOD be pleased to state :

(a) the capacity-wise details of Government stores in the country ;

(b) whether it is a fact that Governmen[1] foodgrain stores have no money and space to purchase and store more foodgrains ; and

(c) if so, whether private agciculturistc: who have money and storage facility for food-grains will be allowed to store and export foodgrains in the liberalized economy?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD (SHRI KALP NATH RAI) : (a) The capacity-wise details of the total storage capacity available with Food Corporation of India for storage of foodgrains as on 1-11-1994 was as under :—

(in lakh tonnes)

	Covered	CAP (Cover and Plinth)
Owned	122.61	14.22
Hired	93.80	36.43
TOTAL :	216.41	50.65

(b) No, Sir.

(c) There arc no stock limits for storage of foodgrains by farmers and they can export foodgrains according to the existing export policy in which export of wheat, rice, coarse-grains and pulses is allowed within fixed quanti-tative ceilings.

मध्य प्रदेश में चीनी एककों की स्थापना हेतु ऋण प्रदान किया जाना

1540. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आगामी वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में स्थापित किये जाने वाले नए चीनी एककों को केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से आवधिक ऋण देने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां तो किन-किन वित्तीय संस्थाओं को आवधिक ऋण संबंधी आवेदन पत्रों के संबंध में कार्यवाही करने को कहा गया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) इन संस्थाओं ने अब तक ऐसे कितने प्रस्तावों पर विचार किया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) वित्तीय संस्थाएं खुद ही नई चीनी इकाईयों को उनकी व्यवहार्यता और उपलब्ध फण्ड के आधार पर आवधिक ऋण उपलब्ध करा रही हैं ।

(ख) और (ग) नई चीनी फैक्टियों को आवधिक ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाएं हैं— आई. एफ. सी. आई., आई डी. पी. आई., आई. सी. आई., सी. आई. सी. आई. और आई. आर. बी. आई. ।

(घ) और (ङ) आई. एफ. सी. आई. द्वारा 1993-94 वर्ष के दौरान भेजी गई सूचना के अनुसार आई. एफ. सी. आई. ने मध्य प्रदेश में नर्मदा शूगर्स लि. को 1000 लाख रुपये का ऋण मंजूर किया था ।

दक्षिणी गुजरात में चीनी मिलों के विस्तार हेतु ऋण प्रदान किया जाना

1541. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को दक्षिणी गुजरात स्थित चीनी मिलों के विस्तार हेतु ऋण को मंजूरी देने के संबंध में गुजरात राज्य सरकार से कोई विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या मिल के विस्तार हेतु वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने के प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सरकार और वित्तीय संस्थाएं कब तक ऋण उपलब्ध करवा देंगी ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) और (ख) चीनी विकास निधि से